2. कृषि बाजारों में पारदर्शिता की अवधारणा

कृषि बाजारों में पारदर्शिता का अर्थ है कि कृषि उत्पादों की खरीद-फरोख्त से संबंधित जानकारी स्पष्ट, सही और समय पर उपलब्ध हो। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बाजार के सभी प्रतिभागियों—जैसे किसान, व्यापारी, खरीदार और सरकारी संस्थाएँ—को कीमतों, मांग, गुणवत्ता मानकों और व्यापार प्रक्रिया से संबंधित समान जानकारी प्राप्त हो सके।

पारंपरिक मंडियों में अक्सर किसानों के पास प्रचलित बाजार कीमतों की विश्वसनीय जानकारी नहीं होती है। कई बार व्यापारी और कमीशन एजेंट मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखते हैं, जिससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। पारदर्शिता की कमी के कारण किसान अपनी सीमित सौदेबाजी क्षमता के चलते अपनी उपज कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हो सकते हैं।

पारदर्शी कृषि बाजार यह सुनिश्चित करते हैं कि किसान अपनी उपज के वास्तविक बाजार मूल्य से अवगत रहें। जब कीमतों की जानकारी खुलकर उपलब्ध होती है, तो किसान विभिन्न बाजारों की कीमतों की तुलना कर सकते हैं और अपनी उपज बेचने के लिए सबसे उपयुक्त बाजार का चयन कर सकते हैं। पारदर्शिता किसानों और व्यापारियों के बीच विश्वास को भी बढ़ाती है, जिससे बाजार की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी और सुचारु बनती है।

पारदर्शिता का एक और महत्वपूर्ण पहलू गुणवत्ता मूल्यांकन है। कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग उनके गुणवत्ता मानकों जैसे आकार, नमी की मात्रा और शुद्धता के आधार पर की जाती है। जब ग्रेडिंग और मानकीकरण पारदर्शी तरीके से किया जाता है, तो किसानों को उनकी उपज की गुणवत्ता के अनुसार उचित मूल्य प्राप्त होता है। इससे किसान बेहतर गुणवत्ता वाली फसल उत्पादन के लिए प्रेरित होते हैं।

आधुनिक तकनीकों जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन नीलामी और मोबाइल एप्लिकेशन ने कृषि बाजारों में पारदर्शिता को काफी बढ़ाया है। ये तकनीकें किसानों को वास्तविक समय (real-time) में कीमतों की जानकारी, डिजिटल लेनदेन का रिकॉर्ड और पारदर्शी बोली प्रणाली प्रदान करती हैं। परिणामस्वरूप किसान बाजार में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं और अपनी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।

Source: Source: https://www.facebook.com/

INTRODUCTION

कृषि कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिनमें भारत भी शामिल है। किसान अपनी उपज बेचने और आजीविका कमाने के लिए कृषि मंडियों (मंडी प्रणाली) पर निर्भर रहते हैं। हालांकि पारंपरिक कृषि बाजारों में कई समस्याएँ पाई जाती हैं, जैसे कि मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता की कमी, बिचौलियों की अधिक भूमिका, सीमित बाजार पहुँच और किसानों को भुगतान में देरी। ये समस्याएँ किसानों के लाभ को कम कर देती हैं और कृषि विकास को भी प्रभावित करती हैं।

कृषि बाजारों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है ताकि व्यापार निष्पक्ष रूप से हो सके और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। पारदर्शी बाजार किसानों को कीमतों, मांग और गुणवत्ता मानकों से संबंधित सही और समय पर जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे किसान बेहतर निर्णय ले सकते हैं। हाल के वर्षों में कृषि विपणन प्रणाली की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों को अपनाया गया है।

भारत में इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) है। e-NAM एक अखिल भारतीय ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो देशभर की कृषि मंडियों को एक डिजिटल नेटवर्क से जोड़ता है। यह किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को ऑनलाइन बोली (bidding) के माध्यम से पारदर्शी तरीके से व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होती है और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।

विभिन्न मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़कर e-NAM किसानों को अपने स्थानीय बाजार से बाहर भी अधिक खरीदारों और बाजारों तक पहुँच प्रदान करता है। इससे किसानों को अपनी उपज के बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त, e-NAM में डिजिटल भुगतान प्रणाली भी शामिल है, जिससे किसानों को समय पर और सुरक्षित भुगतान प्राप्त होता है।

इस प्रकार, पारदर्शिता और e-NAM जैसे डिजिटल विपणन प्लेटफॉर्म कृषि बाजारों के आधुनिकीकरण, किसानों की आय बढ़ाने और भारत की कृषि विपणन प्रणाली को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

Source: https://www.facebook.com/

क्रमांक: COOP/2023/KOTA/201080/26/32

एग्रीकल्चर फ़ोरम फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑफ़ फार्मिंग सोसायटी

कोटा, राजस्थान

कृषक मंडियों में पारदर्शिता और ई-नाम का महत्व

संकलन

डॉ. नेहा द्विवेदी

संविदा शिक्षक, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, आर.वी.एस.के.वी.वी – कृषि महाविद्यालय, इंदौर -452001 मध्य प्रदेश

3. e-NAM (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार

इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य देशभर की कृषि मंडियों को एकीकृत करना और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में शुरू किया गया था, ताकि कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार (Unified National Market) बनाया जा सके।

e-NAM प्लेटफॉर्म APMC मंडियों को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से जोड़ता है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए किसान, व्यापारी और खरीदार कृषि उत्पादों की खरीद-फरोख्त डिजिटल माध्यम से कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि विपणन में पारदर्शी मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करना और विपणन प्रणाली की कमियों को दूर करना है।

इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान विभिन्न मंडियों में उपलब्ध कृषि उत्पादों की वास्तविक समय (real-time) कीमतें देख सकते हैं और ऑनलाइन नीलामी (online bidding) में भाग ले सकते हैं। इससे विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारी प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे किसानों को अपनी फसलों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त होता है।

e-NAM में गुणवत्ता परीक्षण और ग्रेडिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से कृषि उत्पादों का मूल्य उनकी गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसके साथ ही डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से किसानों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त हो जाता है।

4. कृषि बाजारों में e-NAM का महत्व

1.पारदर्शी मूल्य निर्धारण e-NAM के लागू होने से कृषि विपणन प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इसका एक प्रमुख लाभ पारदर्शी मूल्य निर्धारण है। किसान विभिन्न खरीदारों द्वारा दी जा रही कीमतों को देख सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी उपज के लिए उचित और प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलती है।

2. बिचौलियों में कमी पारंपरिक विपणन प्रणाली में किसान अपनी उपज बेचने के लिए अक्सर कमीशन एजेंटों या बिचौलियों पर निर्भर रहते हैं। ये बिचौलिए अधिक कमीशन लेकर किसानों के लाभ को कम कर देते हैं। e-NAM इस प्रकार के बिचौलियों की भूमिका को कम करता है और किसानों को सीधे खरीदारों से जुड़ने का अवसर देता है।

3. बाजार तक विस्तृत पहुँच: e-NAM के माध्यम से किसानों को केवल स्थानीय मंडियों तक सीमित नहीं रहना पड़ता। वे अन्य राज्यों और क्षेत्रों के खरीदारों तक भी पहुँच सकते हैं। इससे उनकी उपज की मांग बढ़ती है और आय के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं।

4.बाजार की दक्षता में सुधार:

यह प्लेटफॉर्म व्यापार प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित बनाकर बाजार की दक्षता बढ़ाता है। ऑनलाइन बोली प्रणाली, डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग और मानकीकृत गुणवत्ता परीक्षण से लेनदेन के दौरान होने वाली देरी और विवाद कम हो जाते हैं।

5. डिजिटल भुगतान की सुरक्षा:

e-NAM के माध्यम से किए गए भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं। इससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होता है

Source: https://biowellorganic.com/

6. बेहतर गुणवत्ता उत्पादन को प्रोत्साहन

e-NAM किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाली फसल उत्पादन के लिए प्रेरित करता है। चूंकि कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग उनकी गुणवत्ता के आधार पर की जाती है और उसी के अनुसार कीमत मिलती है, इसलिए किसान उन्नत खेती तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। 🌾

5. किसानों के लिए पारदर्शिता और e-NAM के लाभ

पारदर्शिता और e-NAM किसानों तथा कृषि क्षेत्र को अनेक लाभ प्रदान करते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ उचित मूल्य (Fair Pricing) है। किसानों को उनकी उपज का मूल्य बाजार की मांग और गुणवत्ता के आधार पर मिलता है, न कि बिचौलियों के प्रभाव के अनुसार।

एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ बाजार की जानकारी तक पहुंच है। किसान वास्तविक समय (Real-time) में वस्तुओं की कीमतों, मांग की प्रवृत्तियों और बाजार की स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी उन्हें यह निर्णय लेने में मदद करती है कि अपनी उपज कब और कहाँ बेचनी है।

e-NAM प्रतिस्पर्धात्मक बोली को भी बढ़ावा देता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। जब कई व्यापारी बोली प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो किसानों को अधिक कीमत मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

यह प्रणाली तेज और सुरक्षित भुगतान भी सुनिश्चित करती है। डिजिटल बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का भुगतान जल्दी और सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त हो जाता है, जिससे उन्हें लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता।

इसके अतिरिक्त, यह प्लेटफॉर्म गुणवत्ता परीक्षण और ग्रेडिंग की सुविधा भी प्रदान करता है, जिससे किसानों को बाजार में आवश्यक गुणवत्ता मानकों की जानकारी मिलती है। इससे किसान बेहतर खेती पद्धतियों को अपनाने और उच्च गुणवत्ता वाली फसल उत्पादन के लिए प्रेरित होते हैं।

पारदर्शिता और e-NAM विपणन प्रणाली में भ्रष्टाचार और हेरफेर को भी कम करते हैं। चूंकि सभी लेन-देन डिजिटल रूप से रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए अनुचित गतिविधियों की संभावना काफी कम हो जाती है।

6. चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ

हालाँकि e-NAM ने कृषि बाजारों में पारदर्शिता को काफी बढ़ाया है, फिर भी इसके सामने कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। प्रमुख चुनौतियों में से एक किसानों में सीमित जागरूकता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के कई किसान अभी तक इस प्लेटफॉर्म के उपयोग और इसकी सुविधाओं के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं रखते हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती डिजिटल साक्षरता की कमी है। कुछ किसानों के लिए स्मार्टफोन या कंप्यूटर का उपयोग करना कठिन हो सकता है, जो e-NAM प्रणाली तक पहुँचने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए किसानों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कृषि विस्तार सेवाएँ बहुत आवश्यक हैं।

इसके अतिरिक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित समस्याएँ, जैसे कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी और अपर्याप्त मंडी सुविधाएँ, भी कुछ क्षेत्रों में e-NAM के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रभावित करती हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल और तकनीकी ढाँचे को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है।

इन चुनौतियों के बावजूद e-NAM का भविष्य बहुत उज्ज्वल और संभावनापूर्ण है। लगातार तकनीकी विकास और सरकारी सहयोग के साथ यह प्लेटफॉर्म और अधिक विस्तार करेगा तथा देशभर के अधिक किसानों और मंडियों को जोड़ेगा।

भविष्य में मोबाइल एप्लिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ब्लॉकचेन तकनीक और लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म जैसी आधुनिक तकनीकों के एकीकरण से कृषि विपणन प्रणाली की दक्षता और पारदर्शिता को और अधिक मजबूत किया जा सकता है।

निष्कर्ष

पारदर्शिता और इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) भारत की कृषि विपणन प्रणाली को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करके e-NAM पारदर्शी मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करता है, बिचौलियों की भूमिका को कम करता है और किसानों के लिए बाजार तक पहुँच को बढ़ाता है।पारदर्शी बाजार व्यवस्था किसानों को कीमतों, गुणवत्ता मानकों और मांग से संबंधित सटीक जानकारी प्रदान करती है, जिससे वे अपनी उपज बेचने के बारे में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बोली प्रणाली विपणन प्रक्रिया की दक्षता और विश्वास को बढ़ाती है।हालाँकि डिजिटल साक्षरता और आधारभूत संरचना जैसी कुछ चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, फिर भी निरंतर तकनीकी प्रगति और सरकारी समर्थन के माध्यम से e-NAM को और मजबूत बनाया जा सकता है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और सतत कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा।